(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1989–90 से 1992–93 के दौरान उत्तर प्रदेश को स्वीकृत/आबंटित वार्षिक अनुदान नीचे दिये गये अनुसार हैं :–

	(करोड़ रु० में)
1989–90(स्वीकृत)	564.80
1990–91(स्वीकृत)	1149.50
1991–92(स्वीकृत)	1351.74
1992–93(आबंटित)	1434.70

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को कोई अल्पावधि ऋण स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of land by A.D.D.A. to R.B.I. at Durgapur

899. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has taken possession of a plot of land allotted by Asansol Durgapur Development Authority for opening of an office of Reserve Bank of India at Durgapur;

(b) if so, what is the date of possession; and

(c) by when the Reserve Bank of India is likely to open the projected office there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that they have acquired land on lease in the Steel township at Durgapur from the Steel Authority of India Limited and taken possession of the same in July, 1984.

(c) Reserve Bank of India do not have any plan for opening of office at Durgapur in the near future.

समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के द्वारा बैंकों में खोले गये खाते

900. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमजोर वर्गों के लोगों तथा कारीगरों, ग्रामीण और लघु उद्योगों के श्रमिकों द्वारा बैंकों में खोले गये खातों की संख्या विगत दो वर्षों की तुलना में कम हो गई है और इन वर्गों के व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की राशि में भी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक इन वर्गों के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन वर्गों के लोगों को अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋण का कम से कम 10% ऋण कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों सहित कमजोर वर्गों को देना अपेक्षित है। जून, 1990 और जून 1991 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान कमजोर वर्गों

और कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित राशि और मार्च 1990 तथा मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक उक्त श्रेणियों के अग्रिमों की बकाया राशि नीचे दी गई है:—

(खाते लाखों में) (राशि करोड़ रु०)

	कमजोर वर्ग		कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	
	खाते	राशि	खाते	राशि
वर्ष 1989–90 (जुलाई–जून) के दौरान संवितरण	57.72	2495.87	2.86	1.49
1990–91 (जुलाई–जून)	53.43	2546.75	3.02	1.89
मार्च 1990 के अन्त तक बकाया	259.01	10110.38	15.34	7.12
मार्च 1991	253.42	10588.69	14.98	7.43

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि कमजोर वर्गों और कारीगरों ग्राम और कुटीर उद्योगों को संवितरित ऋणों और उनके नाम बकाया राशि में वृद्धि हुई है। लेकिन खातों की संख्या में मामूली सी गिरावट आई है। कमजोर वर्गों को ऋण देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक आधार पर सुविधा दी जाती है और यदि किसी कमी का पता चलता है तो उसके लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। हाल ही में सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि वे कमजोर वर्गों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठायें ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का उत्तर प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम

901. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण बैंकों को शाखायें खोलने हेतु जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय औसत निवेश की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य (श्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखायें खोलने के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त 1985–90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान उत्तर प्रदेश में शाखायें खोलने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को 1110 लाइसेंस जारी किये गये थे। इसके अलावा इसी अवधि